रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग). महाराष्ट्र में धूलिया जिले के सोनडेल नामक स्थान पर मिलिटरी स्कूल खोलने के लिए सरकार को प्रस्ताव मिले हैं।

रायगढ़ के समीप मिलिटरी अर्थात् सैनिक स्कूल स्थापित किए जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है ।

रायगढ़ में सैनिक स्कूल स्थापित किये जाने के लिए सुझाव दिये जाने पर यह स्पष्ट किया गया था कि ऐसा स्कूल राज्य सरकार की सिफारिश पर ही स्थापित किया जा सकता है। यह आश्वासन दिया गया था कि राज्य सरकार के अनुरोध पर केन्द्र सरकार ऐसे स्कूल के लिए सामान्यतया दी जाने वाली सहायता देगी ।

Workers Sector for various Mills

410. SHRI SUDHIR GHOSAL: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government propose to set up a workers sector for entrusting the expansion of following spheres of work to this sector:—(1) City Transport, (2) House Building, (3) Rice Mills, (4) Sugar Mills, (5) Oil Mills, (6) Textile Mills, (7) Paper Mills, (8) Brick Industries, (9) Atta Mills, (10) Leather Industry; and

(b) whether Government encourage the workers sector by making credit facilities available from the institutions set up by State and Central Governments?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI): (a) and (b). The Statement on Industrial Policy laid before Parliament on 23rd December, 1977 has clarified Government's policy regarding workers' participation in para 33 thereof. The same is reproduced below:

"33. The most important single resource of any country is the skill and hard work of its people. We, in India, have an abundant supply of labour which is capable of acquiring new skills very quickly and also an existing reservoir of technical and managerial personnel. These resources can be used effectively only in an environment in which the workers and managers develop a sense of personal involvement in the working of the enterprise. Family control of business particularly in the field of large scale industry is an anachronism, and it will be Government's policy to insist on professionalism in management. At the same time, ways and means have to be found to create amongst workers, both in public and private sector industries, a stake in the efficient working of their units.........."

आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से 20 सूत्री कार्यक्रम का प्रसारण

411. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री 8 मार्च, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2080 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 9 जनवरी, 1978 को प्रसारित किए गये 'चिंतन' कार्यक्रम के सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो जिन-जिन वाणिज्य केन्द्रों से यह कार्यक्रम प्रसारित हुआ था, उनके अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) : (क) जी हां ।

(ख) सम्बन्धित प्रोग्राम एक्जीक्यटिव तथा ट्रांसमीशन एक्जीक्यूटिव को क्रमशः "निन्दा" और दो वर्ष के लिए 'वेतन वृद्धियां रोकने" का दण्ड दिया गया है । प्रोडक्शन

असिस्टेंट और उद्घोषक को चेतावनी दी गई है ।

विभिन्न विज्ञापन प्रसारण केन्द्रों में कार्यरत अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करनी आवश्यक नहीं समझी गई, क्योंकि उनको चूक के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया गया था ।

अखबारी कागज का उत्पादन तथा नये कारखाने की स्थापना करना

412. **श्री सुरेन्द्र झा सुमन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय अखबारी कागज बनाने वाले कारखानों की संख्या कितनी है, प्रत्येक कारखाने की वार्षिक उत्पादन क्षमता क्या है और उनकी क्षमता का कितना उपयोग किया जा रहा है ; और

(ख) अखबारी कागज की इस समय देश में कितनी खपत तथा उत्पादन में अन्तर को खत्म करने के लिए कारखाने स्थापित करने की सरकार की कोई योजना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) देश में इस समय अखबारी कागज का उत्पादन करने वाला एकमात्र एकक मैसर्स नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लि0, नेपानगर है । मिल की क्षमता 30,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 75,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष करने का कार्य चल रहा है । इस समय मिल की अधिष्ठापित क्षमता 67,500 मीट्रिक टन अनुमानित है जिसके माध्यम से मिल द्वारा वर्तमान वर्ष में 60,000 मीट्रिक टन का उत्पादन स्तर प्राप्त किये जाने की आशा है ।

(ख) इस समय अखबारी कागज की वार्षिक मांग लगभग 2 लाख मीट्रिक टन है । हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन जो भारत सरकार का एक उपक्रम है केरल राज्य में 80,000 मी० टन वार्षिक क्षमता वाली एक अखबारी कागज परियोजना की स्थापना कर रहा है । परियोजना के वर्ष 1979 को तृतीय तिमाही में चालू हो जाने की आशा है । मैसर्स मैसूर पेपर मिल्स को प्रतिवर्ष 75,000 मीट्रिक टन अखबारी कागज तैयार करने हेतु पर्याप्त विस्तार करने के लिए एक औद्योगिक लाइसेंस प्रदान किया गया है । इस योजना का कार्यान्वयन सक्रिय रूप से किया जा रहा है तथा 1980-81 में इसके चालू हो जाने की संभावना है ।

केन्द्र निदेशकों के पद पर पदोन्नति देने के आधार

414. **श्री नवाब सिंह चौहान** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वाणिज्य केन्द्रों को मुख्य केन्द्र से मिलाकर वहां पर केन्द्र निदेशक के स्थान पर सहायक केन्द्र निदेशक रखने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार, जब तक यह कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती, विभागीय तरक्की पर बनाये गये केन्द्र निदेशकों की नियुक्तियों को रोकने पर भी विचार कर रही है ;

(ग) क्या वर्गीज कमेटी के अनुसार केन्द्र निदेशक किसी भी वर्ग का हो सकता है ; और

(घ) यदि हां, तो एक ही वर्ग के व्यक्तियों को पदोन्नति दिये जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) विज्ञापन प्रसारण केन्द्रों में किस स्तर के व्यक्ति रखे जाने चाहिएं यह समूचा प्रश्न विचाराधीन है ।